



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 अगस्त, 1994/11 आश्विन, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

मण्डी, 26 जुलाई, 1994

संख्या पी०सी०एन०-एम०एन० डी०-ए०(1) 61/92-2710-15.—यतः श्री भाल चन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष पंचायत समिति पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने मुहाल दुवन, तहसील जोगिन्दनगर में स्थित भूमि खमरा नम्बर 2580/2578/1 रकबा तादादी 0-1-0 बोघा मनकीयत हिमाचल प्रदेश सरकार पर अवैध रूप से कब्जा करके गैर मुमकिन स्टोर चादर पोश एक मंजिला निमित किया है, जिसके कारण वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के अधीन पंचायत पदाधिकारी के पद के लिए निरर्हता के अन्तर्गत आ गये हैं;

और यह कि उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज को उप कार्यालय के आदेश संख्या पी०सी०एन०-एम०एन० डी०-ए०(1) 61/92-2547-51, दिनांक 6-7-94 के अन्तर्गत अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था;

और यह कि उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने उपरोक्त आदेश के मन्दर्भ में जो उत्तर इस कार्यालय में प्राप्त हुआ पर विचार किया गया और उत्तर निम्न कारणों से अन्तोपप्रद पाया गया :—

1. श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने प्रस्तुत उत्तर के अन्तर्छेद (1) में व्यक्त किया है कि उसने मुहाल दुवन में खमरा नम्बर 2580/2576/1 रकबा तादादी 0-1-0 बोघा सरकारी भूमि पर कोई भी

नाजायज कब्जा नहीं किया है और न ही कोई स्टोर उक्त जगह पर चादर पोश एक मंजिला है। अतः गिरदावर द्वारा नाजायज कब्जा हटाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यह भी व्यक्त किया है कि उपायुक्त को यह अधिकार भी प्राप्त नहीं कि वह सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी की कार्यवाही को स्वयं करके उस द्वारा किये गये कथित कब्जे को उठाने का आदेश दे। इस तरह का आदेश उपायुक्त के कार्य क्षेत्र से बाहर है।

श्री भाल चन्द्र भारद्वाज का उपरोक्त उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं क्योंकि उन पर सरकारी भूमि खसरा नम्बर 2580/2578/1 पर नाजायज कब्जा करने का आरोप है, जबकि वह खसरा नम्बर 2580/2576/1 पर नाजायज कब्जा न करने की बात कह रहे हैं। उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने दिनांक 18-4-85 को सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्दरनगर के समक्ष अपने ब्यान में उपरोक्त सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा उठाने से सम्बन्धित चल रही कार्यवाही में यह ब्यान किया है कि कथित भूमि पर उसके भाई ने कब्जा कर रखा है और उसने नहीं। परन्तु यह भी ब्यान किया है कि वह उक्त नाजायज कब्जे को सरकारी शीपधालय बनने के बाद उठा देंगे। अतः स्पष्ट है कि उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने ही सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। केवल अपने बचाव के लिए अपने भाई का इसमें संनिप्त कर रहे हैं।

2. श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने अपने उत्तर के अनुच्छेद (2) में यह व्यक्त किया है कि श्री कश्मीर सिंह राजपूत द्वारा इन्हीं विषयों पर अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष चुनाव याचिका दाखल की है, यह तथ्यों पर आधारित नहीं, क्योंकि जो चुनाव याचिका कश्मीर सिंह राजपूत द्वारा उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज के विरुद्ध दायर की है, में उनके सरकारी कर्मचारी होने का आरोप है न कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने का;

और यह कि श्री भाल चन्द्र भारद्वाज खसरा नम्बर 2580/2578/1 तादादी 0-1-0 बीघा भूमि मन्कीयत हिमाचल प्रदेश सरकार पर नाजायज कब्जा न करने के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके;

और यह कि उक्त श्री भाल चन्द्र भारद्वाज ने मुहल्ला दूबल में स्थित खसरा नम्बर 2580/2578/1 तादादी रकबा 0-1-0 बीघा भूमि पर मन्कीयत हिमाचल प्रदेश सरकार पर अवैध कब्जा करके तथा उक्त भूमि पर अवैध निर्माण करके हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत पंचायत का पदाधिकारी बनने की निरहता के अधीन हो गये हैं।

अतः मैं, तरुण श्रीधर (भा० प्र० से०), उपायुक्त मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) (ii) में निहित हैं, विनिश्चित करता हूँ कि श्री भाल चन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष पंचायत समिति चोन्तड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 उप-धारा (1) (ग) के अन्तर्गत निरहता के अधीन है जिसके कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 131 (1) के अन्तर्गत पंचायत समिति चोन्तड़ा, जिला मण्डी में श्री भाल चन्द्र भारद्वाज का अध्यक्ष व प्राथमिक सदस्य के पदों को रिक्त घोषित करता हूँ। यह आदेश तुरन्त प्रभावी माने जायेंगे।

तरुण श्रीधर,

उपायुक्त,

मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be eligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be *Ex-servicemen* recruited under the provisions of rules of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of *Ex-servicemen* (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1983 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(b) Similarly, in all cases of confirmation, *ad hoc* service rendered in the feeder post upto 31-3-1991, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that *inter-se* seniority as a result of confirmation after taking into account *ad hoc* service rendered upto 31-3-1991 shall remain unchanged.

Note.—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rules are persued.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.

Not Applicable.